भारत सरकार

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 158

03.02.2025 को उत्तर देने के लिए

वृहद आर्थिक (मैक्रोइकॉनोमिक) डेटा जारी करने में देरी

158. श्री मल्लिकार्जुन खरगेः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा जीडीपी के आंकड़ों जैसे प्रमुख वृहद आर्थिक डेटा जारी करने में देरी के क्या कारण हैं;

(ख) सरकार इन देरियों को दूर करने और भविष्य में ऐसे महत्वपूर्ण डेटा के प्रकाशन के लिए समय अंतराल को कम करने की किस तरह से योजना बना रही है;

(ग) क्या सरकार ने डेटा संग्रह और प्रसंस्करण के तेज प्रसार को कारगर बनाने के लिए नई पद्धतियों या प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर विचार किया है; और

(घ) निवेश, व्यवसाय और नीतिगत निर्णयों में सहायता के लिए वृहद आर्थिक डेटा की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) और (ख): सकल घरेलू उत्पाद, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जैसे प्रमुख वृहद आर्थिक आंकड़ों का अनुमान सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित अग्रिम रिलीज कैलेंडर (एआरसी) के अनुसार जारी किया जाता है।

(ग) और (घ): राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली में सामंजस्यपूर्ण गुणवत्ता रिपोर्टिंग को बढ़ावा देने के लिए डेटा संरचना का मानकीकरण और प्रशासनिक डेटा का उपयोग द्वारा डेटा संग्रहण तथा एआरसी के अनुसार प्रसार को कारगर बनाने हेतु उठाए गए प्रमुख कदम हैं। मैक्रोइकॉनोमिक डेटा विभिन्न डेटा स्रोतों का उपयोग करके और निर्धारित मानकों को अपनाकर संकलित किए जाते हैं, जो मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

****